**महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा**

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

**जनसंपर्क कार्यालय**

**PUBLIC RELATIONS OFFICE**

## नारी शक्ति वंदन अधिनियम : महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम

## महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में परिसंवाद में शिक्षिकाओं ने साझा किए विचार

**वर्धा, 12 अप्रैल, 2026:** महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में शनिवार, 11 अप्रैल को 'महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' विषय पर परिसंवाद का आयोजन किया गया जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की महिला

संकाय सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अधिनियम के व्यावहारिक क्रियान्वयन और इसके सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों पर अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाषा विद्यापीठ की अधिष्ठाता प्रो. प्रीति सागर ने की। परिसंवाद में डॉ. हर्षलता पेटकर,डॉ. गौरी शर्मा, डॉ. सीमा बर्गट, डॉ. सारिका राय शर्मा, डॉ. पुष्पा नामदेव, डॉ. मैत्रेयी, डॉ. रेणु सिंह, प्रयागराज क्षेत्रीय केंद्र से डॉ. आशा मिश्रा, डॉ. अवंतिका शुक्ला, डॉ. सुप्रिया पाठक, कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र से डॉ. चित्रा माली ने आदि ने इस बात पर जोर दिया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक विधायी सुधार नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की संरचना में महिलाओं की निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक दस्तावेज है।

राजनीतिक नेतृत्व और सहभागिता पर विभिन्न विभागों की शिक्षिकाओं ने रेखांकित किया कि विधानसभाओं और संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से नीति-निर्धारण के स्तर पर महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोणों को प्रमुखता मिलेगी। चर्चा के दौरान यह सुझाव आया कि इस अधिनियम की सफलता के लिए शैक्षणिक संस्थानों को 'राजनीतिक साक्षरता' और 'नेतृत्व प्रशिक्षण' के पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षिकाओं ने सुझाव दिया कि आरक्षण के लाभ को 'ग्रास-रूट' यानी जमीनी स्तर की महिलाओं तक पहुँचाने के लिए तंत्र को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने की आवश्यकता है।

सभी शिक्षिकाओं ने माना कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। यह अधिनियम महिलाओं को 'अधिकार' से 'नेतृत्व' की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

---

**पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत**

**ई-मेल/E-mail:** pro.mgahv@hindivishwa.ac.in **वेबसाइट/Website:** **www.hindivishwa.org**

**दूरभाष : +91-7152-252651 मोबाइल/Mobile : 9960562305**

परिसंवाद के अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे विमर्श न केवल विद्यार्थियों को जागरूक करते हैं, बल्कि नीतिगत सुधारों के लिए एक बौद्धिक धरातल भी तैयार करते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉ. किरन कुंभरे ने किया। उन्होंने

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की जानकारी दी। अधिनियम के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साहित्य विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो. अवधेश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर शिक्षक, कर्मचारी शोधार्थी और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

**नारी शक्ती वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरणाचे: एक क्रांतिकारक पाऊल आहे**

**हिंदी विश्वविद्यालयातील शिक्षिकांनी आपली मते मांडली**

**वर्धा, १२ एप्रिल २०२६ :** महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयात शनिवार, ११ एप्रिल रोजी 'महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३' या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. या परिसंवादात विश्वविद्यालयातील विविध विभागांतील महिला प्राध्यापकांनी सक्रिय सहभाग घेत अधिनियमाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसह त्याच्या सामाजिक-राजकीय परिणामांवर आपले महत्त्वपूर्ण मत मांडले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाषा विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता प्रो. प्रीती सागर होत्या.

या परिसंवादात डॉ. हर्षलता पेटकर, डॉ. गौरी शर्मा, डॉ. सीमा बर्गट, डॉ. सारिका राय शर्मा, डॉ. पुष्पा नामदेव, डॉ. मैत्रेयी, डॉ. रेणु सिंह, प्रयागराज प्रादेशिक केंद्रातील डॉ. आशा मिश्रा, डॉ. अवंतिका शुक्ला, डॉ. सुप्रिया पाठक तसेच कोलकाता प्रादेशिक केंद्रातील डॉ. चित्रा माली यांनी सहभाग नोंदवला. सर्वांनी यावर भर दिला की 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हा केवळ कायद्यातील बदल नसून भारतीय लोकशाहीत महिलांची निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करणारा ऐतिहासिक दस्तावेज आहे. राजकीय नेतृत्व आणि सहभागाबाबत विविध विभागांतील महिला प्राध्यापकांनी नमूद केले की विधानसभांमध्ये आणि संसदेत ३३ टक्के आरक्षणामुळे धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत महिलांचे अनुभव आणि दृष्टीकोन अधिक प्रभावीपणे समोर येतील. चर्चेदरम्यान असेही सुचविण्यात आले की या अधिनियमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शैक्षणिक संस्थांनी 'राजकीय साक्षरता' आणि 'नेतृत्व प्रशिक्षण' यांसारख्या

**पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत**

**ई-मेल/E-mail:** pro.mgahv@hindivishwa.ac.in **वेबसाइट/Website:** **www.hindivishwa.org**

**दूरभाष : +91-7152-252651 मोबाइल/Mobile : 9960562305**

अभ्यासक्रमांवर विशेष भर द्यावा. तसेच आरक्षणाचा लाभ तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्याची गरज असल्याचेही मत व्यक्त करण्यात आले.

सर्व सहभागी प्राध्यापकांनी एकमताने सांगितले की 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हा भारताच्या विकास प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. हा अधिनियम महिलांना 'अधिकार' पासून 'नेतृत्वा'कडे वाटचाल करण्यास मार्गदर्शन करतो.

परिसंवादाच्या शेवटी असा निष्कर्ष काढण्यात आला की विद्यापीठ स्तरावरील अशा चर्चांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता वाढते आणि धोरणात्मक सुधारणांसाठी बौद्धिक पायाभूत आधार तयार होतो. कार्यक्रमाचे संचालन डॉ. किरण कुंभरे यांनी केले. त्यांनी 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३' विषयी सविस्तर माहिती दिली. अधिनियमाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. साहित्य विद्यापीठाचे अधिष्ठाता प्रो. अवधेश कुमार यांनी आभार प्रदर्शन केले. यावेळी शिक्षक, कर्मचारी, शोधार्थी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

**Nari Shakti Vandan Act: A Transformational Step Toward Women Empowerment**
**Faculty members share insights at a symposium in MGAHV**

**Wardha, April 12, 2026:** A symposium on the topic 'Nari Shakti Vandan Act 2023' from the Perspective of Women Empowerment" was organized on Saturday, April 11, at Mahatma Gandhi International Hindi University. Women faculty members from various departments actively participated and presented their valuable suggestions on the practical implementation of the Act and its socio-political impact.

The program was chaired by Prof. Preeti Sagar, Dean of the Faculty of Languages. Participants included Dr. Harshalata Petkar, Dr. Gauri Sharma, Dr. Seema Bargat, Dr. Sarika Rai Sharma, Dr. Pushpa Namdev, Dr. Maitreyi, Dr. Renu Singh, Dr. Asha Mishra and Dr. Avantika Shukla from the Prayagraj Regional Centre, Dr. Supriya Pathak, and Dr. Chitra Mali from the Kolkata Regional Centre, among others. All emphasized that the Nari Shakti Vandan Act is not merely a legislative reform but a historic document aimed at ensuring decisive participation of women in the structure of Indian democracy. Highlighting political leadership and participation, faculty members noted that the provision of 33% reservation in legislative assemblies and Parliament would bring women's experiences and perspectives to the forefront of policymaking. During the discussion, it was suggested that for the successful implementation of this Act, academic institutions should focus on courses related *to* political literacy *and* leadership training.

The participants also stressed the need to make the system more transparent and accessible so that the benefits of reservation reach grassroots-level women effectively. All faculty members agreed that the Act would prove to be a milestone in India's development journey, paving the way for women to move from rights *to* leadership. The symposium concluded with the observation that such discussions at the university level not only raise awareness among students but also create an intellectual foundation for policy reforms. The program was coordinated by Dr. Kiran Kumbhre, who also provided an overview of the Nari Shakti Vandan Act 2023. The event commenced in accordance with the guidelines of the Act. Prof. Avdhesh Kumar, Dean of the Faculty of Literature, delivered the vote of thanks. A large number of teachers, staff members, research scholars, and students were present on the occasion.